Shrimati Savitri Nigam (Banda): His remarks should be expunged. (*Interruptions.*)

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Whatever he has said should be expunged.

Mr. Speaker: These words need not be put in the proceedings

12.22 hrs.

STATEMENT *RE*: GOVERNMENT'S POSITION ON CHINESE AGGRESSION

Mr. Speaker: The Prime Minister.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Dr. Ram Manohar Lohia and Sarvshri Prakash Vir Shastri and S. M. Banerjee have expressed the view in their Motion that there have been some contradictory statements regarding China's aggression and claims on our territory. I cannot help feeling that this is based on some misunderstanding and I, therefore, take this opportunity of restating our position on this question in order to remove any such misunderstanding.

Some time after the Chinese had committed aggression on our borders, the Colombo Proposals were formulated by certain friendly countries. The Government of India accepted these proposals, but the Chinese Government did not do so. Later, the Ceylonese Prime Minister consulted us on the question of Civilian Check-Posts in the demilitarised zone of Ladakh. In reply the Government of India indicated their willingness to agree to there being no posts of either side in the said demilitarised zone. Since then there have been no further developments. In this context, the question of any negotiations does not arise at present.

The Government of India believe in the pursuit of peace and in settlement by mutual discussions, provided always that such discussions can be held consistently with the honour and dignity of the country.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, on a point of clarification. Does the Government, adhere firmly to the policy laid down earlier in the time of the late Prime Minister—many of us on this side differ from that policy also, but at least that minimum which they proclaimed then—that they will not depart a jot or a tittle from the Colombo proposals and, if it is not so, to what extent is the Government proposing to climb down?

Shri Lal Bahadur Shastri: Our position in regard to the Colombo proposals is quite clear. We stick to what the late Prime Minister had said, that we cannot go beyond what the Colombo proposals contain.

श्री मधु लिमये (मुंगर) : इधर एक अर्से से चीन को लेकर हमारी सरकार एक फिसलन के रास्ते पर चल रही है । प्रधान मंत्री ने कई बार कहा था कि जब तक चीन हमारे प्रदेश से हट नहीं जाता है तब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी । लेकिन हमने देखा कि फिर 8 सितम्बर को सीमा की बात चली । उसके बाद यह कोलम्बो प्रस्ताव आये फिर उसके बाद यह नया सुझाव आया है कि अगर हिन्दुस्तान अपनी वहां चेकपोस्ट नहीं बनायेगा तो चीन भी और चक पोस्ट्स नहीं बनायेगा और इस तरह बातचीत हो सकती है । इस तरह एक फिसलन के रास्ते पर हम जा रहे हैं । यह भी कहा जाता है कि अणु विस्फोट करके चीन ने

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल कर लें इस तरह से भाषण न देते चले जायें ।

श्री मधु लिमये : यह कहा गया कि चीन ने अणु विस्फोट करके मानव जाति का अपमान किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार चूंकि चीन ने समस्त मानव जाति के विचारों और राय का यह

[श्री मधुलिमये]

विस्फोट करके अपमान किया है, कोई एक स्पष्ट नीति बनायेगी और क्या भारत सरकार चीन के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये तत्काल तैयार है ?

दूसरी बात मेरी यह है और वह उससे सम्बन्ध रखती है

अध्यक्ष महोदय : लिमये साहब, मैं यह आपका भाषण आखिर कब तक सुनता रहूं ?

श्री मधु लिमये : सम्मानपूर्वक समझौता करने की जो बात की जाती है कि हम चीन के साथ सम्मानपूर्ण समझौता करेंगे तो उसमें भारत माता की भूमि का उसके किसी एक हिस्से का सौदा तो नहीं होगा, इसका मैं प्रधान मंत्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जब यह बातचीत चले तब पता चलेगा कि क्या बहस मुबाहसा होता है अभी मैं इस बारे में कैसे कह सकता हूं ?

श्री मधु लिमये : क्या भूमि का सौदा करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : भूमि देने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है बाकी जैसा कि मैंने कहा अभी सदन में यह कह सकना कठिन है कि क्या बहस मुबाहसा होगा ।

Shri Swell (Assam—Autonomous Districts): The late Prime Minister had offered to take this question of the dispute with China to the International Court at the Hague and this House has approved of that. There was a report that a similar proposal that an impartial, third party under the auspices of the United Nations must go into this question and demarcate the area. Has the Government refused that . . .

Mr. Speaker: He is having such a long introduction. I am requesting the Members to be brief.

Shri Swell: May I know the reasons which persuaded the Government to accept the first proposal and to refuse the second proposal?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला । मैंने पूछा था कि सरकार यह अणु विस्फोट को लेकर चीन के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध का विच्छेद करने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को सवाल करने की इजाजत दी । उन्होंने सवाल कर लिया और जवाब भी आ गया ।

श्री मधु लिमये : लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । इस तरीके से कार्यवाही कैसे चल सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो चुका जवाब भी आ गया । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री मधु लिमये : आप प्रधान मंत्री से कहें कि वे मेरे प्रश्न का साफ़ और स्पष्ट जवाब दें । इस तरीके से सवालों से भागना अच्छा नहीं है । इस में सदन का अपमान होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर इस तरीके से माननीय सदस्य चलते रहे तो हाउस की कार्यवाही नहीं चल सकेगी ।

श्री मधु लिमये : सदन की कार्यवाही चलाने में मैं आप की सहायता करना चाहता हूं लेकिन मैंने जो सवाल उठाया है प्रधान

मंत्री उस का जवाब नहीं दे रहे हैं । जब वे कहते है कि अणु विस्फोट कर के चीन ने मानव जाति का अपमान किया है तो मैं जानना चाहता हूं क्या वह चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए तैयार हैं .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब आना ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये इस सदन् की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं आप की मदद करना चाहता हूं । आप प्रधान मंत्री जी से कहें कि वे जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इन का नाम ले कर

श्री मधु लिमये : सारा देश जानना चाहता है । उस का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्य का नाम लेकर यह कहता हूं कि श्री मधु लिमये जानबूझ कर इस सदन् की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे हैं और उस को रोक रहे हैं इसलिए मैं उन को कहता हूं कि वह सदन् से बाहर चले जायें ।

(Shri Madhu Limaye then left the House).

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैं यह मोशन रखता हूं कि इधर पिछले तीन, चार रोज से आये दिन यह जो कुछ माननीय सदस्यों के हाउस से निकाले जाने की घटनाएं हो रही हैं प्रतीत ऐसा होता है कि वे इसलिए निकलना चाहते हैं ताकि अखबारों में रोज उन के बारे में चर्चा आती रहे इसलिए इन घटनाओं का समाचार अखबारों में न छापा जाय ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : मैं भी इस का समर्थन करता हूं कि यह खबर अखबारों में नहीं निकलनी चाहिए ।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): When the motive is *bona fide*, it is all right. But when the motive is *mala fide*, this House has got and you have also got the power that this matter may not be reported in the press. The *mala fide* purpose is also served if it is published.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Regarding the suggestion made by my hon. friend, Shri Kachhavaiya that news of this kind should not be given prominence in the Press, I submit that this House has no power, and if this House has any power, this power should not be used to restrict the freedom of the Press. The Press has its own conscience, has its own rules and has its own ways of selecting what should be played up in the Press and what should not be played up in the Press. We may appeal to them, but beyond that we may not go.

श्री अ० प्र० जैन : इस हाउस को हमेशा इस बात का अख्त्यार है कि वह इस बात को रोक सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से इत्तिफ़ाक करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं ।

श्री अ० प्र० जैन : हाउस को हमेशा इस बात का अख्त्यार है कि इस किस्म की हिदायत प्रेस को दे सके । कुछ सदस्यों ने इस बात का तहैया कर लिया है कि वे यहां पर इस किस्म की कार्यवाहियां करें, जिस से सदन की कार्यवाही न चल सके और उन को पब्लिसिटी मिले ।

श्री किशन पटनायक (संबलपुर) : यह ग़लत बात है ।

श्री अ० प्र० जैन : जो सदस्य इस तरह की कार्यवाही कर के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमें उन को इस तरह फ़ायदा उठाने से रोकना चाहिए । यह बड़ा मुनासिब होगा कि प्रेस को यह हिदायत दी जाये कि यहां पर महज पब्लिसिटी के लिए जो इस किस्म की कार्यवाही हो रही है, उस को न छापा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहां यह एहसास हुआ कि बाज़ वक्त ऐसी बातें इस ग़रज़ से की जाती हैं कि वे अखबारों में छप सकें । मेम्बर साहब ने इस बारे में एक मोशन भी दी है । इस से मुझे वाकई बहुत तसल्ली हुई है और मेरा खयाल है कि बाकी माननीय सदस्य इस से इत्तिफ़ाक करेंगे, लेकिन मेरा खयाल यह है कि जल्दी में हमें ऐसी पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए । जब ऐसे लोग बिल्कुल ज्यादा ऐसे काम करते जायेंगे, तो पब्लिक भी अपने आप उस का अन्दाजा लगाती जायेगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वक्त इस पर ज्यादा ज़ोर न दिया जाये और न इस पर और डिस्कशन किया जाये ।

Dr. Swell: The Prime Minister was going to reply to my question, Sir.

Mr. Speaker: That has been lost now.

Shri Hari Vishnu Kamath: He may repeat it.

Shri Nath Pai (Rajapur): The Prime Minister has made an important statement and today is the last day of this session. Will you please permit us to put a few questions, Sir?

Mr. Speaker: Yes, Dr. Swell may repeat his question.

Dr. Swell: May I know what are the reasons which persuaded the Government to accept the late Prime Minister's proposal to take this question of our dispute with China to the International Court at the Hague and dissuaded the Government from accepting a similar proposal that an impartial third party under the auspices of the UN may be requested to go into the question of our border dispute with China and to demarcate it on scientific lines?

Shri Lal Bahadur Shastri: Firstly, I do not know who makes that proposal and who has made that proposal. If there is no such specific proposal from any quarter, why should we raise it and discuss it?

Dr. Swell: Yesterday the Foreign Minister in the other House had referred to it.

Mr. Speaker: No further arguments. Mr. Nath Pai.

Shri Nath Pai: Every time a reference is made about Government's intention with regard to negotiations with China, the Prime Minister and other spokesmen of the Government say this simple thing that we are pledged to peaceful negotiations and we shall not do anything which may infringe the honour and dignity of the country. We are sure that he would be bearing in mind the honour of the country. But what we are worried about is the territorial integrity of the country. Will the Prime Minister make a categorical assurance to this House that no agreement will be reached with China which may involve in any way giving even an inch of the territory of the country? (*Interruptions*).

Shri Lal Bahadur Shastri: There is no question of any negotiation just at present. All these things could arise when a discussion takes place or it is fixed (*Interruptions*).

Shri Nath Pai: Sir, I admire the parliamentary skill which Shri Shastri and his colleagues are evolving in avoiding replies to our questions (*Interruption*). Sir, I want you to help us. What hindrance is there, what comes in the way of giving this solemn assurance to Parliament that no negotiations will be entered into, no agreement will be reached which

may involve our territory? My emphasis is only on peace, dignity and honour (*Interruptions*).

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I rise to a point of order. You have ruled times without number that the minister's answers should be precise, concise and very clear. Now my hon. colleague, Shri Nath Pai's question, was whether the Government will give an assurance that not an inch of territory will be bargained or negotiated away. The Prime Minister said that we are not to negotiate at present and all these questions will arise, if I heard him right, when we go to the table, when we go to negotiate. That means he has got at the back of his mind the possibility of this question arising. Therefore, we want to know the Government's attitude at this stage.

Mr. Speaker: Inferences and interpretations are for hon. Members to draw.

Shri Hari Vishnu Kamath: That shows the unclarity of the answer. It is the most vital issue for the country, for India, for our motherland. (*Interruptions*). There is profound silence on the Treasury Benches. Parliament had pledged itself, had passed a resolution on 14th November, 1962.

Shri Nath Pai: Sir, you are so indulgent that you are persisting in looking this side that the Prime Minister is failing to catch your eye. He has been looking towards you for allowing him to give a reply to my question. (*Interruptions*).

Shri Hari Vishnu Kamath: May your glance fall on him also.

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि जब तक चीन भारतीय धरती से नहीं हट जाता है, तब तक उस के साथ बातचीत का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उस के बाद जो स्थितियां बदली हैं उन में दो तीन प्रकरण इस प्रकार के आए हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन का समझौता होना, जिस में चीन के द्वारा उस भारतीय धरती पर अपना अधिकार करने की बात कही गई है, जिस पर पाकिस्तान गैर-कानूनी क़ब्जा किए हुए है, नेफ़ा और लद्दाख के कई लाख वर्ग-मील हिस्से पर चीन का दावा और तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में कोलम्बो-प्रस्ताव-देशों की जो बैठक प्रधान मंत्री बुलाना चाहते थे, चीन द्वारा उस को न होने देना, . . .

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य तो यह मिसाल कायम करें कि सवाल मुख्तसर हो । इतना बड़ा स्टेटमेंट कर के सवाल पूछना ठीक नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इन परिस्थितियों में मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जबकि चीन का रुख धीरे-धीरे और बिगड़ने की ओर है, और कड़ा तथा कड़वा होने की ओर है, तब भारत सरकार अपने पुराने समझौतावादी और समन्वयवादी रुख़ को कब तक कायम रखेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जो हमारा निश्चय है, उस निश्चय को और कोलम्बो प्रोपोज़ल्ज़ को पार्लियामेंट ने भी माना है । हम उन प्रस्तावों पर कायम हैं और अगर कोई कार्यवाही होने वाली है, तो वह उन प्रस्तावों के अनुसार ही होगी ।

Shri Kapur Singh: Sir, I appreciate your indulgence in permitting me to have it on record that, so far as this part of the House is concerned—I may not speak for the entire House—the reply which the hon. Prime Minister has given to the question put by Shri Nath Pai has left us not only unsatisfied but uneasy too.

Shri U. M. Trivedi: The question which has been put is a very pertinent question but the reply that has been given . . .

Mr. Speaker: What is the question? Let him ask it.

Shri U. M. Trivedi: I am not putting any embellishment to it. I want to know definitely and categorically from the Prime Minister what prevents him from giving a categorical answer to a categorical question that not an inch of land will be surrendered to China while negotiating. This is a very pertinent question and a categorical answer is called for, particularly in view of the diabolical reply that he has given today which will cause unrest in the minds of the public at large.

Shri Lal Bahadur Shastri: We are not going to give up our Indian territory. But it is true that the Colombo Propsals are there and we have to keep them in mind.

श्री किशन पटनायक : यह मानते हुए कि दूसरे माननीय सदस्य लोग जो भाषण यहां देते हैं या सवाल करते हैं वे अखबार में उसे छपवाना नहीं चाहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने अभी जो बयान दिया वह डा० लोहिया, श्री शास्त्री और श्री बनर्जी के जिस प्रस्ताव को आप ने ऐडमिट किया था उस में सिर्फ एक तिहाई का उत्तर दिया, दो तिहाई पर कुछ नहीं कहा । मैं ने आप को आज पत्र भी लिखा था और मछली बाजार के स्पष्टीकरण के बारे में उस में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उस का जवाब तो मैं ने दे दिया है । अब और समय मैं इस में नहीं लगा सकता ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : एक प्रश्न मुझे भी पूछ लेने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त बस ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं सीधा प्रश्न पूछूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी, आप के आगे तो मुझे झुकना ही पड़ता है ।

श्री रामेश्वरानन्द अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा झुकता रहा हूं । अब भी मैं आप की आज्ञा से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मगर इस इकरार पर कि आगे जब मैं कहूंगा तो उस वक्त आप झुक जायेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द : चीन का हमारे प्रति पहले से भी कठोर व्यवहार है और हमारी भूमि पर भी उस का अधिकार है । हमारे पड़ोसी देशों से भी उस ने सम्बन्ध स्थापित किया है । इन हालात में भी हम चीन के साथ बात चीत करने के लिए तैयार हैं तो क्या इस से हमारा सम्मान यथापूर्व रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : बतलाइये प्रधान मंत्री साहब ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री हां । मैं समझता हूं कि इस में कोई असम्मान या अनादर की बात नहीं है । हमारी एक नीति है कि अगर कोई बात सुलह से तय हो सकती है तो हम उस को तय करना चाहते हैं । बाकी इस में हमारी कोई इज्जत घटेगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं है । बल्कि उस से हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ी ही है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, . .

अध्यक्ष महोदय, बस स्वामी जी, मैं ने आप से इकरार ले लिया था । अब आप को नहीं पूछना चाहिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : इसी बात पर ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी नहीं । अब आप बैठ जाइये ।

Now the Finance Minister.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Mr. Speaker, Sir..

Shri J. B. Kripalani (Amroha): Sir, I have been standing for some time.

Mr. Speaker: I am sorry. I have already passed on to the next subject. It will create great difficulties for me. So, I would request the hon. Member to resume his seat.

Shri J. B. Kripalani: Sir, I rarely get up, and whenever I try to catch your eye, I miss it. It is my misfortune.

12.50 hrs.

STATEMENT RE: ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Hon. Members would recall that in the last session of the Parliament I had occasion to review economic conditions in the country. During the current session the House has had several opportunities for discussing the emergent economic situation, particularly in regard to agricultural prices. The steps we have taken, and propose to take, to increase agricultural production and to regulate the distribution of agricultural commodities have also been the subject of discussion both in this House and outside. My intention in making a statement in the House today, however, is to deal with some other areas which have an equal bearing on the health of the economy.

2. The steps we took during the first two years of the current plan period to overcome the shortage of transport, power and coal have had a salutary effect on industrial production. Despite the difficulties created by the Chinese attack on our borders, industrial production in 1963-64 increased by 9.2 per cent as against an increase of 8 per cent in 1962-63 and 6.4 per cent in 1961-62. It is too early yet to forecast the outlook on industrial production for the current year as a whole. It is, however, clear that in many of our important industries we have now reached a situation where further increases in production will depend materially on our ability to bring new capacity into operation as soon as possible. In the public sector, programmes for expansion in a number of basic industries, such as steel and machine building, are well under way. In the private sector also arrangements for licensing establishment of new capacity as well as for providing foreign exchange for the import of equipment have been completed. Simultaneously, we have taken many steps, such as the establishment of the Development Bank and the Unit Trust, to provide adequate resources for the promotion of industrial activity.

3. Nevertheless, it is generally felt—and this feeling is to a large extent true—that the investment climate is not there, that is, there is something lacking in our present arrangements for stimulating a greater flow of savings into industrial investment. While these arrangements are fairly adequate in regard to loan finance which along with internal resources of industry constitute a very important element in industrial investment, the lacuna in respect of individual investment in equities is there. But in a community in which we seek to extend the area of participation by the people in industrial expansion, there is need for greater stimulation of investment in equities. I feel that our present arrangements in this regard are not adequate. As the House is aware the state of the capital market for equity issues, particularly those of new issues, is far from encouraging. A large proportion of equity issues has had to be taken up by under-writers in the recent past. The main reason for this is that the investing classes, particularly those with modest means, find it difficult to wait for several years without any return on their investment in the shape of dividends. Those who cannot afford to wait at all, prefer